

**ग्रामीण कार्य विभाग**  
**बिहार सरकार**

**आदेश**

आ०सं० :-3/अ०प्र०-1-58/14

4116

/पटना, दिनांक :- 23.1.2020

स्व० सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ, नालंदा के विरुद्ध पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में निगरानी थाना कांड सं०-026/2010 दिनांक 15.04.2010 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा 1(ई) दर्ज किये जाने के कारण पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-344-सह-पठित ज्ञापांक 4908 दिनांक 30.11.2010 द्वारा श्री सतीश कुमार सिंह के विरुद्ध अभियांजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। कालान्तर में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 1450(एस०) दिनांक 20.02.2014 द्वारा अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के पश्चात श्री सिंह का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग हो जाने के कारण संबंधित संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

2. संचिका के समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-026/2010 दिनांक 15.04.2010 दर्ज किये जाने के कारण विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-36-सह-पठित ज्ञापांक 2051 दिनांक 03.07.2014 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया एवं आरोप पत्र प्रपत्र-'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-53-सह-पठित ज्ञापांक 3110 अनु० दिनांक 04.09.2014 द्वारा श्री धर्मदेव चौधरी, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 031 दिनांक 16.03.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप संख्या-1 को अप्रमाणित परन्तु यह मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण न्यायालय के अंतिम पारित आदेश इसके फलाफल पर अक्षर-सह-प्रभावी होने को मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुए श्री सिंह के विरुद्ध पुनः कार्यालय आदेश संख्या 32-सह-पठित ज्ञापांक 2077 अनु० दिनांक 15.06.2015 द्वारा श्री चन्द्रशेखर साहु, अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 121 अनु० दिनांक 15.09.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जिसमें निष्कर्ष के रूप में आरोप संख्या-1 को अप्रमाणित, आरोप संख्या-2 में आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान अस्वीकार योग्य एवं आरोप संख्या-3 को न्यायपालिका के अंतिम पारित आदेश/फलाफल अनुसार प्रभावी होने का मंतव्य दिया गया।

4

2

4. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षापरान्त असहमति संशोधित करते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 63 अर्जुं दिनांक 04.01.2016 द्वारा असहमति के बिन्दुओं के आलाोक में द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

श्री सिंह द्वारा विभागीय पत्रांक 63 अर्जुं दिनांक 04.01.2016 से पूछे गये द्वितीय ब्याव बयान को माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1161/2016 द्वारा चुनौती दी गयी एवं विभाग को अप्सवेदन समर्पित करते हुए पन्द्रह दिनों का अतिरिक्त समय की मांग की गयी।

5. श्री सिंह द्वारा विभागीय निदेश के बावजूद द्वितीय ब्याव बयान समर्पित नहीं किये जाने के कारण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय निर्णय लेते हुए बिहार सरकारों सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (X) के तहत पूर्वतन दंड के रूप में सेवा से बर्खास्तगी की शक्ति अधिरक्षित करने का प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अर्जमादन शक्ति अधिरक्षित एवं संशोधित की गयी।

6. श्री सीरीश कुमार सिंह, सेवा से बर्खास्त कनीय अभियंता द्वारा माननीय न्यायालय में दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1161/2016 पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा श्री सिंह को निदेश दिया गया कि बर्खास्तगी आदेश 447 दिनांक 25.01.2016 के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रखें। श्री सिंह द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में एल०पी०ए० संख्या-1900/2016 दायर किया गया। उक्त दायर एल०पी०ए० पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि परिवर्ती अपना पक्ष अपीलीय प्राधिकार के समक्ष रखें या पुनः सी०डब्ल्यू०जे०सी० दायर करें, जिसकी सुनवाई की जायेगी।

7. श्री सिंह द्वारा पुनः माननीय न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-210/2017 दायर किया गया। जिसपर सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 69-सह-पठित ड्रापंक 447 दिनांक 25.01.2016 को निरस्त करते हुए अधिकृत किया गया कि श्री सिंह के विरुद्ध श्री धर्मदेव चौधरी, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन संशोधित प्रथम विभागीय कार्यावली में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष-आरोप संख्या-2 एवं 3 का मतलब:- किसी सरकारों सेवक पर इस तरह के मामला दर्ज होने पर सरकार एवं विभाग की छवि एवं प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इस प्रकार का आवरण अनुशासन के विरुद्ध है। परन्तु यह मामला माननीय न्यायालय में विचारणीय है। न्यायापालिका के अतिम पारित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही इनके दोष पर विचार किया जा सकता है।

आरोप संख्या-1-आरोपित कनीय अभियंता श्री सीरीश कुमार सिंह के ब्याव बयान पर विचारपरान्त यह स्पष्ट होता है कि इन पर आरोप प्रमाणित नहीं होता है, परन्तु यह मानना न्यायालय में विचारणीय रहने के कारण न्यायालय के अतिम पारित आदेश इसके

14/10/2017

अतएव उक्त आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 में निहित प्राधान्य के आलोक में आलोच्य मामले को संचिकास्त करते हुए स्व. सतीश कुमार सिंह के निधन अवधि (दिनांक 10.07.2014 से 25.01.2016) एवं बख्तरनी अवधि (दिनांक 26.01.2016 से 18.04.2017) को कर्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतनादि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा उक्त अवधि को विनियमित की जाती है।

11. चूंकि श्री सतीश कुमार सिंह के मृत्यु हो जाने की सूचना कार्यालयक अभियोगा कार्यालय, झंझारपुर के माध्यम से विधिवत रूप से विभाग को प्राप्त है

उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जाएगा।  
सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का में निहित प्राधान्यसंग आरपी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में संबंधित हुई। मृत कर्मियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 कार्यालय, झंझारपुर के पत्रांक 829 अर्जु दिनांक 12.07.2019 द्वारा विभाग को प्राप्त 2019 की मृत्यु हो जाने की विधिवत सूचना कार्यालयक अभियोगा, प्रथम क्रम विभाग, कालांतर में श्री सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियोगा की दिनांक 12.07.

न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलफल से प्रभावित होने का आदेश दिया गया।  
2010 अख्तियार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा 1 (ई) में साथ ही उक्त आदेश को निगरानी थाना काड संख्या-026/2010 दिनांक 15.04.

निष्कर्ष से सहमत होते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया।  
निरस्त करते हुए श्री सिंह के विरुद्ध संचालित प्रथम विभागीय कार्यवाही के प्रतिवेदन के के तहत पारित वृहत् शक्ति आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (X) प्राधिकार द्वारा श्री सतीश कुमार सिंह, तदन कनीय अभियोगा समिति बख्तर के विरुद्ध संख्या-301-सह-पठित शापांक 769 दिनांक 19.04.2017 द्वारा अभियोगा प्रमुख/सक्षम 9. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सरकार आदेश

करे।  
प्राधिकार विभागीय कार्यवाही को चालू रखे या बंद कर दें, परन्तु अंतिम निर्णय संसंधित  
8. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया कि अनुशासनिक प्राधिकार को निर्दिष्ट किया गया।

फलफल पर अक्षरशः प्रभावी होगा। आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक

23/1/2020  
 1

आभियंता प्रमुख  
 23/1/2020

आभियंता प्रमुख  
 पटना/दिनांक :- 23-1-2020  
 116  
 3/अ०प्र०-1-58/14  
 प्रतिनिधि :- आई०टी० मैनजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय  
 वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

आभियंता प्रमुख  
 23/1/2020

आभियंता प्रमुख  
 पटना/दिनांक :- 23-1-2020  
 116  
 3/अ०प्र०-1-58/14  
 प्रतिनिधि :- प्रधान सचिव, निर्याती विभाग(निर्याती अन्वेषण ब्यूरो), बिहार,  
 पटना/ आभियंता प्रमुख, पशु निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन  
 विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य आभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण  
 आभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, दरभंगा/उप सचिव, ग्रामीण कार्य  
 विभाग/कार्यपालक आभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर/प्रशाखा  
 पदाधिकारी-4/स्व० सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन कर्मीय आभियंता, राष्ट्रीय उच्च पशु  
 प्रमंडल, बिहारशरीफ, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी, पञ्जाब का  
 पता-ग्राम-नया टोला, सारिस्ताबाद, आजमगढ़, पशु, प०/14, प०-जी०पी०आ०।  
 ग्राम-गढ़नीबाग, पिन कोड-800001 को सर्वनाथ प्रेषित।

आभियंता प्रमुख  
 पटना/दिनांक :- 23-1-2020  
 116  
 3/अ०प्र०-1-58/14  
 प्रतिनिधि :- कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सर्वनाथ एवं आषटक कार्डाई हेतु  
 प्रेषित।